Goa, the responsibility lies with the Government of that Union Territory. It is up to them to consider it. I have already said, the modified Draft Bill will be cleared after proposed discussions with the administration.

SHRI EDUARDO FALEIRO: In view of the special needs of the Union Territory and in view of the special facilities required for specialised education, may I know whether Government will make substantial grants for the setting up of this university in Goa, which can be a model university for the rest of the country? Because, Sir, we don't want mere multiplicity of universities in the country for producing more and more of graduates. But we want a model university on special subjects. So will the Government make substantial grants and allocation of funds for a good university and a model university to be established there? Will it be in the State sector or Central sector?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Regarding establishment of universities in this country the primary responsibility for the setting up of university is that of the State Government. I think this is known to the hon. Member. Once it is established the Government will come forward to help it.

SHRI EDUARDO FALEIRO: That is not the question. Sir, there are universities like Jawaharlal Nehru University and some other universities which are Central Universities, which are set up or established by the Central Government. But there are other universities which are established by the State Governments. Is this University going to be established by the Central Government or by the State Government?

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: By the State Government.

SHRI Y. S. MAHAJAN: Will it have important facilities like Engineering and medicine?

MR. SPEAKER: Next question.

आलू का मूल्य

622. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसल कटने के समय आलू का मूल्य इतना गिर जाता है कि किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता;

(ख) क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत आलू उत्पादकों का लाभकारी मूल्य मिल सके ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Available data on prices reveal that prices of potato at the time of harvest temporarily fall as compared to the prices prevailing during the other months due to heavy market arrivals. The wholesale prices of potato in different months during the current year have ruled higher as compared to those of last year. Comparison of market prices of potato with their cost of production in surplus potato growing areas is not possible as cost of production data for potato are not available.

(b) and (c). Assurance of remunerative price to the producers of agricultural commodities is a major objective of the Government's price policy. When the prices of potato show a downtrend, purchases are made by NAFED from areas of surplus production of potato for distribution in consuming centres and for export. During the year 1978-79, purchases made by NAFED were of the order of 75,000 tonnes and the exports during the same year were around 16,000 tonnes. In the following year 1979-80, NAFED had procured a quantity of about 22,000 tonnes out of which about 10,000 tonnes were exported. These measures have played a significant role in providing better returns to the producers.

श्री विजय कुमार यादव : मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए एक बात जो कहीं है कि फालतू आलू पैदा करने वाले क्षेत्रों में आलू के बाजार मूल्यों की उसकी उत्पादन लागत से तुलना करना संभव नहीं है, सरकार के पास बहुत बड़ी मशीनरी

आंकड़े इकट्ठे करने के लिए है, फिर ऐसा क्यों नहीं संभव है? उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि हार्वेस्टिंग के समय बाजार में आलू की भारी आमद होने की वजह से कीमतों में अस्थायी रूप से गिरावट आती है। मंत्री महोदय ने मेरे ही एक अनस्टार्ड क्वश्चन नं० 4010 के जवाब में कहा था कि आलू की पैदावार में हर साल बढ़त हो रही है। उन्होंने खुद बताया कि 1976-77 में 71.70 लाख टन और 1977-78 में 81.35 लाख टन....

अध्यक्ष महोदय: हो गई बढ़ोतरी अब सवाल कीजिये।

श्री विजय कुमार यादव: मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने कबूल किया है कि हर साल उसकी बढ़त होती है। उत्तर के भाग (ख) और (ग) में जो जवाब उन्होंने दिया है, उसमें बताया है कि 1978-79 में 75 हजार मीट्रिक टन आलू नाफेड के द्वारा खरीदा गया और 16 हजार मीट्रिक टन एक्सपोर्ट किया गया लेकिन दूसरे साल यानी 1979-80 में केवल 22 हजार मीट्रिक टन की खरीद नाफेड के द्वारा की गई और 10 हजार टन निर्यात किया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आलू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए जब आप इस बात को कबूल करते हैं कि हर साल आलू का उत्पादन बढ़ता जा रहा है तो फिर 1978-79 के मुकाबले 1979-80 में आपने कम आलू की खरीद नाफेड के द्वारा क्यों की और एक्सपोर्ट कम क्यों की?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह चाहती है कि आलू का एक्सपोर्ट वह बढ़ाये, जिसमें किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके तो क्या आलू पर आधारित उद्योग भी हिन्दुस्तान में खड़ा किया जा सकता है या नहीं? हमको याद है कि 1975 में अलबानिया या किसी दूसरे मुल्क ने हिन्दुस्तान से समझौता करने के लिए कहा था कि वह आलू पर आधारित उद्योग खड़ा करने के लिए हिन्दुस्तान की मदद करेगा, इस सिलसिले में सरकार क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: यह सवाल करने वाला का आपका कोई तरीका नहीं है।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव): आलू की खरीद तब शुरू की जाती है जब इसके भाव बहुत ज्यादा गिरने लग जायें ज्यादा पैदावार की वजह से। जब कभी सरकार ने देखा कि आलू के भाव इतने नीचे गिर गये हैं कि किसान को उनकी मेहनत का मुआवजा भी नहीं मिलता, तो नाफेड के जरिये से आलू की खरीद शुरू की जाती है। साथ ही साथ यह भी देखना पड़ता है कि आलू का भाव इतना न चढ़ जाये कि डोमैस्टिक माकट में हमारे अपने खाने के लिए इतनी महंगाई हो कि खा ही न सकें, तक्लीफ कंज्यूमर्स को हो। इन दोनों चीजों का ध्यान रखा जाता है। इस लिए किसी साल में आलू की खरीद ज्यादा हुई और किसी में कम हुई।

दूसरे आलू पैरीशेबल होता है, इसके लिए हमारे पास ज्यादा स्टोर नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा खरीदा नहीं जा सकता है। किसी ऐसी मिकदार में ही आलू खरीदा जा सकता है, जिससे भावों को सहारा भी मिल जाये और खराब भी न हो और नाफेड को ज्यादा नुकसान भी न हो।

जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव की बात है कि ऐसे कारखाने लगाये जायें, जिससे आलू का प्रोसेसिंग हो जाये, सरकार का ध्यान उस तरफ है, हम आगे प्लान बना रहे हैं कि जो सबजियां पैरीशेबल हैं, उनका इस्तेमाल हो सके, उनके भाव भी ठीक हो सकें, उसका ध्यान रखा जाता है। इस साल आलू का भाव काफी बढ़ रहा है, इतना नीचे नहीं गिरा जिस भाव पर नाफेड पहले खरीदे और जो सपोर्ट प्राइस नाफेड की रही है, उससे ज्यादा भाव जुलाई के महीने में हिन्दुस्तान में आमतौर पर सब मंडियों में चल रहे हैं, ऐसी हालत में आलू की खरीद का सवाल ही नहीं।

MR. SPEAKER: Before you put the supplementary, Mr. Yadav, I would like to bring to the notice of this august House that I take a very serious note of the fact that certain Members abstain from the House after tabling their questions. This has been a regular practice. This causes a loss to the public exchequer and it is our duty that we should make ourselves present here. Secondly, I would like to mention that the supplementary should be pungent, straight and direct: it should not be this sort of statement. This also takes much time of the House and I do not like it.

श्री विजय कुमार यादव: खाद, डीजल और सिंचाई के रेट में बढ़ोतरी होने से आलू के उत्पादन का लागत खर्च बढ़ रहा है। किसानों की लगातार मांग रही है कि आलू का भाव 75 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित किया जाये, जिससे उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सके। क्या सरकार आलू का भाव 75 रुपये प्रति क्विंटल – जिस समय वह पैदा होता है– निश्चित करने पर विचार कर रही है?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव: सरकार तो आलू का भाव मुकरर नहीं करती है। वह तो किसानों को माकट में सपोर्ट देती है, ताकि उन्हें नुकसान न हो। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, इस साल जब से आलू की फसल आनी शुरु हुई है, तब से उसके भाव बढ़त ही गये हैं। यू० पी० में फर्रुखाबाद में, जहां आलू काफी पैदा होता है, मार्च में आलू का भाव 65 रुपये प्रति क्विंटल था और अब वहां

130 रुपये प्रति क्विंटल के करीब भाव चल रहा है। इसी तरह से पंजाब में मार्च में भाव 75 रुपये था और अब जुलाई में वह 125 रुपये प्रति-क्विंटल चल रहा है। बगलौर में और दूसरी जगहों में भी —सब जगह—भाव काफी बढ़ गया है।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: The Minister in his reply has stated that sometimes when potatoes and other agricultural goods come to the market just after harvesting, at that time the prices are rather below the remunerative price, and even below the cost price. This is because the potato traders in collusion with the cold storage owners want to purchase potatoes at a very low price at that time and store them in the cold storages. They sell these later when the prices go up. The Minister has stated that it was a perishable commodity and there was not sufficient storage capacity. I would like to know whether he will devise some method so that the grower can get the remunerative price at the time of harvesting and the consumer gets the potatoes at a cheap price throughout the year. For this purpose, will the Government construct cold storages in a massive way as also nationalise the private cold storages functioning in our country? I want a categorical answer

SHRI BIRENDRA SINGH RAO: During the last year, the total production of potato has gone up by about 10 lakh tonnes. The productivity per hectare has also increased from 115 quintals to 122.28 quintals per hectare. In spite of that, as I stated just now, the prices now ruling in the market are quite remunerative. I may assure the hon. Member that this Government will not allow potato to rot. Kisans will get remunerative price and as soon as the market crashes, NAFED will move in to purchase the potatoes. That time has gone when potatoes were rotting during the Janata regime. This will not be allowed to happen again.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: My question has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या आप और कोल्ड स्टोरेज बनाने की कोशिश करेंगे।

SHRI BIRENDRA SINGH RAO: Yes; we are aware of the need to set up more storage capacity for potatoes and for other produce. I do not, however, know what the hon. Member means by the nationalisation of private cold storages.

डा० राजेन्द्र कुमार बाजपेयी : माननीय, कृषि मंत्री जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि जब आलू प्रारंभ में मार्केट में आता है तो उस की कीमत बहुत कम हो जाती है और बाद में बढ़ती है, तो सपोर्ट प्राइस शुरु मे ही इस तरह की वह डिक्लेयर करेंगे जिस से कि आरम्भ से ही किसानों को ठीक प्राइस मिले क्योंकि सपोर्ट प्राइस का सम्बन्ध दोनो पक्ष से है, एक तरफ कन्ज्यूमर से भी है और दूसरी तरफ प्राड्यूसर से भी है। तो आप एक निश्चित पालिसी जैसे राइस या व्हीट के लिए तय करते है उसी तरह प्रत्येक साल स्टडी कर के एक सपोर्ट प्राइस आलू के लिए भी आरम्भ में ही डिक्लेयर करेंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सपोर्ट प्राइस का सवाल तब पैदा होता है कि जब किसी चीज की कीमत मार्केट में कास्ट प्राइस से नीचे चली जाय और किसान को नुकसान होने लगे। इस साल जब से आलू मंडी मे आया है कास्ट प्राइस से ऊपर उस की प्राइस रही है यानी प्राइस रेम्युनरेटिव रही है। इसलिए सपोर्ट प्राइस इर्रलिवेंट हो जाती है। प्राइस तो गवर्नमेंट इसलिए देती है कि किसी हालत मे भी किसान को नुकसान न होने पाए। एक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार मुकर्रर करती है वह किसान के लिए इन्श्योरेन्स है कि वह अपनी पैदावार करता रहेगा, उस को बढ़ाएगा तो उस को नुकसान नही होने पाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : मंत्री जी ने कुछ जगहों में जो आलू की कीमत अभी है उस के बारे मे कुछ बात कही। लेकिन मंत्री जी को मालूम होगा कि पटना शहर और बिहार शरीफ जहा से माननीय सदस्य श्री विजय कुमार यादव जी आए, हैं, वहा बहुत ज्यादा तादाद मे आलू पैदा होता है और इसलिए उन्होने यह सवाल भी किया, तो और कई जगहो के बारे मे तो उन्होने 105, 103, या 75 कीमत चल रही है यह बताया, लेकिन और कई क्षेत्र हैं कि जहां आलू ज्यादा पैदा होता है, उन क्षेत्रों के बारे में क्या स्थिति है जिस में पटना भी शामिल है और बिहार शरीफ भी शामिल है या और भी इलाके शामिल होंगे जहां फालतू आलू पैदा होता है, वहां कीमतों की स्थिति क्या है। इस के अलावा जो आलू उत्पादक किसान अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखता

है उसका किराया उस को बहुत ज्यादा देना पड़ता है तो क्या सरकार उस किराये को नियंत्रित करने के बारे में कुछ सोच रही है या सोचने का विचार रखती है ताकि किसानों को ज्यादा किराया न देना पड़े ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : बिहार के बारे में और पटना के बारे में कि वहां आलू का क्या भाव है, वह जानकारी तो मेरे पास इस समय नहीं है लेकिन आम तौर पर जो मैं ने फिगर्स दी है बंगलौर, पंजाब, दिल्ली फर्रुखाबाद जो आलू का बहुत बड़ा सेंटर है और दूसरी जगहों की, जहां आलू ज्यादा से ज्यादा पैदा होता है, जैसे फर्रुखाबाद है, बंगलौर है, दिल्ली है, पंजाब भी कुछ मंडियां हैं, हिमाचल प्रदेश भी है, उन के अंदर बढ़ती हुई और फर्म प्राइसेज को देख कर यह मैं कहा सकता हूं यकीन के साथ कि आलू की कीमत सब जगह अच्छी है और रेम्युनरेटिव प्राइस किसान को मिल रही है। कोल्ड स्टोरेज के किरायें का जहां तक सवाल है तो ऐसी हालत तो हम आइन्दा कभी पैदा होने नहीं देंगे जैसी कि दो साल पहले थी कि आलू की कीमत तो थी 15 रुपये बैग मंडी में और कोल्ड स्टोरेज वाले चार्ज करते थे 25 रुपये, वह भी कभी नहीं होगी। अगर बदकिस्मती से ऐसी हालत होगी तो हम इस के ऊपर भी ध्यान देंगे और कोल्ड स्टोरेज का भी इंतजाम करेंगे मुनासिब किराये पर ।

PLI Policies for Staff of Nationalised Banks and Public Sector Undertakings

*623. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of CMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that although the employees of Reserve Bank and State Bank of India are eligible to take out Postal Life Insurance policies, the staff of the other nationalised banks and public sector undertakings are out of the purview of the Postal Life Insurance scheme; and

(b) if so, will the Government indicate reasons therefor and take action to extend Postal Life Insurance to all such organisations which will be beneficial for the Postal Life Insurance fund and the beneficiaries as well?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KARTIK ORAON): (a) Yes, Sir.

(b) The Life Insurance Corporation of India which was established in 1956, has the exclusive privilege of carrying on life insurance business throughout India. It is only by way of exception that Postal Life Insurance has been permitted to carry on its operations, the consideration being that it provides life insurance cover as a service facility mainly to Government servants. Having regard to the purpose for which the LIC was established, it has not so far been considered necessary to enlarge the scope of the Postal Life Insurance and extend the same to employees of public sector undertakings, including nationalised banks. A suggestion for such extension is, however, being examined.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह बात सही है कि जीवन बीमा का काम करने का क्षेत्र जीवन बीमा निगम का है लेकिन सरकार ने इन्तजाम किया है कि सरकारी कर्मचारियों को कुछ लाभ हो सके इसलिए उनको परमिट किया है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैं जानना चाहूंगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी है या बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी हैं वे भी अर्ध–सरकारी कर्मचारी के बराबर है ही तो उनको आप ऐसी सुविधा देने में क्यों हिचकिचा रहे हैं ? क्या कारण है कि आप उनको देना नहीं चाहते हैं ? उनको देने से लाइफ इंश्योरेन्स को लाभ होगा या नुकसान होगा इसलिए आपको हिचकिचाट है ?

SHRI KARTIK ORAON: This question of the life insurance has a history behind it. The Reserve Bank employees were eligible for PLI prior to the Independence and this facility was extended to the State Bank employees in 1957. The question whether the employees of public undertakings and the Nationalised Banks will be eligible is entirely dependent on the decision of the Ministry of Finance. The Postal Life Insurance is a Government run insurance scheme meant essentially for Government employees of all categories including employees of the State Governments, local bodies and government aided educational institutions, universities, etc. The staff of the CSIR, ISI, Medical Council of